

Folder No. 1

~~1966~~

~~S. No. 397~~

~~File Code 88~~

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस

ALL-INDIA TRADE UNION CONGRESS

RANI JHANSI ROADI NEW DELHI-1.

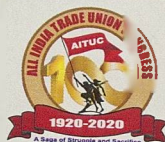
~~I.C on~~

~~Cement~~

~~1966~~

File No

~~199~~



AITUC DIGITAL ARCHIVE - 2021

Folder Code: 1 File No. AI-109 S. No. _____

Digital File Code: _____

File Title: AITUC CONSTITUTION

Year: 1 / 1 / _____

Metadata: Scanned:

Note: _____

~~1956~~

~~1966~~

~~1~~

0

N. Satyanarayana Reddy.
Hyderabad Dn.

I
Amendments to the Constitution 27th May 1956.

General Council and Trade Groups.

9. a:

After (c) Include

1) Cement Group.

Note:- Because: There are 29 cement factories in India and about 60 thousand workers are employed.

- The Cement Unions including INTUC and Independent, have organised the All India Cement Worker Federation.

18 Unions are affiliated to it.

The below stated Unions have been working with INTUC.

		Members.	Workers.
Hyderabad.	1) Shahabud Cement workers Union.	2119	3000
PEPSU.	2) Bhupendro:	1500	2700
Hodnas	3. Madhukari.		2400
Bombay.	4. Sevadis.	1112	1800
Andhra.	5. Kaitna	1200	1800
Or.	6. Andha.	1062	1400
T.C. State.	7. Kottayam ALWAYS:	1000	1500

Some of these Unions might have not had a formal affiliation form and fee but they have been working as INTUC Unions and workers know that their Unions are affiliated to INTUC.

Problems of Cement workers are different from the Quarry workers.

And hence, A Cement Group should be included.

RAJASTHAN TRADE UNION CONGRESS

(Affiliated to A.I.T.U.C.)

Ref No.

Diggi Bazar

AJMER 195

The all India Trade Union Congress
24th Session, Calcutta
28.5.24

Notice of the Amendment in the
Constitution -

See B(b) of the Constitution
should be read thus - The general coun-
cil shall meet at least twice a year.

Kumarama D.

Prova - Rajasthan

दिनांक

सीमान्त प्रधान मंत्री आल इंडिया

ट्रेड यूनियन कांग्रेस

पता: राधेनाथ जायसवाल

११२ नया पुरा नं. १ इन्दौर

मार्फत: अनारकल सेक्रेटरी मध्य भारत ट्रेड
यूनियन कांग्रेस.

विषय :- कमिटी का प्रतिनिधि कौन हो ?

भारतीय गणराज्य में औद्योगिक कमिटी की दैनिक शिकायतों व सामुहिक विवाद बाधक कमिटी की शौर से प्रतिनिधि धत्व करने का अधिकार के बारे में जाप की मौजूदा पद्धति साम तौर पर कमिटी को अन्तर्गत जनक एवं विरोधी तत्वों को कमिटी में भारतीय सरकार के खिलाफ अन्तर्गत भड़काने में सहायक सिद्ध हुई है, वाले राष्ट्र पिता गांधीजी के सिद्धान्तों के अनुसार एवं गणतंत्रिक देश में गणतंत्रिक ढंग से कमिटी के तबाल पर प्रतिनिधीत्व करने का अधिकार कमिटी को ही दिये जाने के उद्देश्य से भारतीय सरकार व राज्य सरकारों द्वारा निम्न रीति से कमिटी के प्रतिनिधीत्व के लिये विधान बनाया जावे.

विधान

१. नामकरण :- इस विधान का नाम ' औद्योगिक विवाद सम्बन्धी कमिटी के प्रतिनिधीत्व का विधान ' रहे.
२. सीमा :- यह विधान मध्य भारत के समस्त उद्योग धन्दों के ऐसे कारखानों में किन्में १ हजार से उपर अधिक कार्य करते हों, उन सभी में प्रभावशील हों.
३. उद्देश्य :- कमिटी के औद्योगिक विवादों को दैनिक शिकायतों को औद्योगिक कानूनों के अन्तर्गत वैधानिक रीति से शान्तिमय व उपायों द्वारा निपटारा करने के लिए कमिटी की शौर से प्रतिनिधीत्व करने का अधिकार प्रदान करना.
४. अधिक :- अधिक से मतलब ऐसे सभी कमिटी से है जो कि इस विधान के अन्तर्गत सीमा में बाने वाले उद्योगों के कारखानों, मालों के बहातों में काम करने वाले कमिटी में अपने ज्योड : मत : से जुना हों, ब्यवा कमिटी द्वारा जुनी गई बाता : डिपार्टमेंटल : पंजायत, फेक्टरी या कारखाना पंजायत या केन्द्र मंडल पंजायतों द्वारा नियुक्त कमिटी की शौर से पेरवी करने वाले प्रतिनिधी से होंगे.
५. औद्योगिक विवाद :- से मतलब ऐसे सभी विवादों से जो कि दैनिक शिकायतों, व्यक्तित्व रूप में या सामुहिक रूप में है शौर सामुहिक तबालों से है.
६. प्रतिनिधी :- का अर्थ ऐसे प्रतिनिधी से है जिसे कारखाना, फेक्टरी

में काम करने वाले अधिकों ने अपने वोट : मत : से जुना हों, अथवा अधिकों द्वारा जुनी गई ताता : डिपार्टमेंटल : पंचायत, फेक्ट्री या कारखाना पंचायत या केन्द्र मंडल पंचायतों द्वारा नियुक्त अधिकों की शौर से पैरवी करने वाले प्रतिनिधी से होंगे.

७. ताता : डिपार्टमेंटल : पंचायत में उसे कहा जाएगा जिसे उस डिपार्ट के समस्त अधिकों ने अपने वोट : मत : से जुना हों, ऐसे इस ताता पंचायत के प्रतिनिधी सदस्यों की संख्या उस डिपार्ट के समस्त जावरों की संख्या के बराबर हों, उन प्रत्येक प्रतिनिधी को उसके जावर के ताते के समस्त च्यायी एवं तीन वर्षों पुराने उस ताते के बदली वाले अधिक अपने वोट से जुनें.

८. छोटे डिपार्ट में जहां के जावरों की संख्या सिर्फ १ ही हों उनमें से दो प्रतिनिधी जुने जावे.

९. प्रतिनिधीत्व के उम्मीदवार की योग्यता में हर एक प्रतिनिधी के उम्मीदवार की योग्यता उस अधिक की नौकरी स्थायी हों अथवा तीन वर्षों पुराना बदली वाला होना आवश्यक हों.

१०. ताता पंचायत कमेटी में समस्त जावरों द्वारा जुना हुआ १ जावर प्रतिनिधी ताता पंचायत का सदस्य लिया जावे, छोटे डिपार्ट जिनमें सिर्फ १ जावर ही हों ऐसे कम से कम ४ डिपार्ट पीछे १ जावर प्रतिनिधी उस ताता पंचायत में लिया जावे.

११. ऐसी जुनी हुई ताता पंचायत में से सब प्रतिनिधी अपने वोटद्वारा ताता पंचायत के पंच और सर पंच का चुनाव करें.

१२. ताता पंचायत प्रतिनिधी के काम का अधिकार में अपने अपने चुनाव स्थल के अधिकों की दैनिक शिकायतों अथवा सामुहिक प्रश्नों को जहां तक हों सके हल करने का प्रयत्न करना और हल हो जाने या नहीं हो सकने की पूरी हुकना अपनी ताता पंचायत के पंच और सरपंच को देना.

१३. पंच और सर पंच का काम यह देखना होगा कि अधिकों की कठिनाईयों को उसके प्रतिनिधी द्वारा दूर की जा सकी है अथवा नहीं १ अगर नहीं तो उसे दूर कराने में भरसक प्रयत्न करना और शिकायतों कठिनाईयों को डिपार्टमेंट आफिसर मिल लेबर आफिसर द्वारा हल कराना, अपने समस्त कार्यों की लेखी रिपोर्ट मील कारखाना पंचायत के अधिकारियों को देना.

१४. प्रत्येक प्रतिनिधी को अधिकों की फ्लॉर के काम का प्रतिनिधित्व करने में उसके काम का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई में उसे प्रतिमाह ५ रुपया पंचायतलाउन्स मिले, ताता पंचायत की बैठके या औपचारिक विवाद में लेबर कोर्ट आदि में उसे जाने की हुक में मैनेजमेंट द्वारा काम से हट्टी दी जाकर उसके उस दिन के वेतन की भरपाई मिलना चाहिये.

१५. ताता पंचायत की साधारण बैठक हफ्ते में एक बार और असाधारण बैठक कभी भी उस ताता पंचायत के सरपंच या पंच के दस्तखतों से बुलाई जा सके

साता पंचायत के चारों कामों का रिकार्ड डे पंच के अधीन रहेगा.

१६. मील कारखाना या फैक्ट्री पंचायत ५ कारखाने का हर एक स्थायी एवं तीन वर्ष पुराना बक्की वाले अधिक भूखे छोटे च्चारा मील फैक्ट्री या कारखाना पंचायत का जवाब दोगी. ऐसी पंचायत में सदस्य संख्या समस्त साता पंचायतों के समस्त प्रतिनिधियों के १/५ संख्या इतनी तादाद हो. जिनके निच निच क्षेत्र की सीमा बना दी जावे. ५

१७. फैक्ट्री कारखाना पंचायत का जवाब होने पर वे उसे वे गये सदस्य भूखे छोटे च्चारा भूखे में से पदाधिकारियों का जवाब करेंगे.

१८. फैक्ट्री कारखाना मंडल पंचायत की साधारण सभा १५ दिन में एक बार होवे और आवश्यकता पर साधारण बैठक मंडल के संपंच के हस्ताक्षरों से और उनका हस्तक्षेप में किसी पंच के हस्ताक्षरों से जुटाई जा सकती है.
 के निम्न पदाधिकारी रहेंगे: -
 एक कारखाना मंडल संपंच ३ पंच और १ पंच में के जेजे की ओर से का जवाब मंडल पंचायत के होंगे.
 R.S. Jaiswal

१९. फैक्ट्री कारखाना मंडल पंचायत की साधारण सभा १५ दिन में एक होवे और आवश्यकता पर साधारण बैठक मंडल के संपंच के हस्ताक्षरों से और उनका हस्तक्षेप में किसी पंच के हस्ताक्षरों से जुटाई जा सकती है.

२०. मंडल पंचायत के काम का रिकार्ड १ पंच के अधीन रहेगा और उसे ही मंडल की हर एक बैठक जुटाने का अधिकार हो.

२१. फैक्ट्री कारखाना मंडल पंचायत के काम और अधिकार :-

:१: डिपार्टमेंटल : साता पंचायत : के कामों में मदद देना. उनके च्चारा चार्ज हुए शिकायतों कठिनाइयों को डिपार्टमेंटल आफिसर लेबर आफिसर मैनेजमेंट गवर्नमेंट लेबर आफिसर अथवा अन्य सम्बन्धित सरकारी अधिकारियों च्चारा उन्हें दूर कराना.

:२: अधिकारों के मुकदमों भूखे या भूखे च्चारा नियुक्त अधिकारी के जरिये लेबर कौर्ट या इन्डस्ट्रियल कौर्ट में पेशी करने का अधिकार मंडल पंचायत को होना चाहिये. किन्तु वे मुकदमों उसी मंडल पंचायत के अधिकार क्षेत्र की सीमा के अन्दर के हों. बड़ी मांगें जुनियादी ऐसे क्वालिफिकेशन के उद्योग के समस्त स्थानीय कारखानों के अधिकारों से हों तो उस उद्योग के समस्त मंडल पंचायतों की जुनी हुई स्थानीय अधिकार केंद्र मंडल पंचायत को ही उसका प्रतिनिधित्व करने का अधिकार रखा जावे.

:३: अधिकारों की कठिनाइयों पर मैनेजमेंट की व्यवस्था पर अत्यंत ध्यान रखकर उद्योग और अधिकारों के हित में काम करना.

:४: मंडल पंचायत को मैनेजमेंट अथवा डिपार्टमेंट के मस्टर और कामजात देखने तथा समस्त जानकारी प्राप्त करने का अधिकार रहना चाहिये.

:५: मैनेजमेंट च्चारा उस कारखाने में किसी नई नियुक्ति या कोई छेद फेर के पूर्व मंडल पंचायत को बुकना पाने का हक होना आवश्यक है. ऐसे मामलों में मंडल पंचायत के प्रस्ताव और को छेद फेर या नियुक्ति नहीं की जा सके.

- :६: अपनेअमलत कामों की रिपोर्ट केन्द्र मंडल पंचायत को देना आवश्यक हो,
 :७: किन्ही सार सलाहकार परिस्थिती में समस्त प्रतिनिधी मंडल की आवश्यक बैठक बुलवाकर विचार करना,
 :८: धारा सभा या लोक सभा एवं सरकारों से अधिकों के हित में कानून बनवाने के लिये अपने सुपचार्य पैसों का अधिकार मंडल पंचायत को हो,
 :९: अपनी मांगों को मनवाने के सभी दरवासे बन्द होने की स्थिती में फैक्टरी पंचायत को हलाल पुकारने का अधिकार रहे.

२२. मंडल पंचायत की हर एक बैठक की अध्यक्षता मंडल के सरपंच करेंगे व उनकी अनुपस्थिती में मंडल के कोई पंच करेंगे.

२३. मंडल पंचायत के सदस्यों को उनकी पंचायत के काम के फल स्वरुप उनकी रोजी में होने वाली सुझानी की भरपाई के लिये १० हजार रुपये मासिक क्लाइन्स पाने का प्रत्येक सदस्य को अधिकार हो तथा मंडल के विशेष कार्यकाल मित से गैर हाजिरी की पूरी भरपाई दी जावे.

२४. मंडल पंचायत और सारा पंचायत के समस्त प्रतिनिधीयों को मिलने वाले क्लाइन्स और गैर हाजिरी की भरपाई तथा मंडल के कार्य एवं स्थानीय केन्द्र मंडल को दिये जाने वाले सर्व की पूर्ति के हेतु उस कारखाने के समस्त अधिकों के वेतन से १ घाना प्रति माह काटा जावे और बाकी सर्व की पूर्ति मैनेजमेंट से कसूल की जावे.

२५. मंडल पंचायतों के काम में होने वाले व्यय व गैर कामद की रकम तथा स्थाय मंडल पंचायत के बाधीन रहेगा.

२६. सारा पंचायत या मंडल पंचायत के समस्त प्रतिनिधीयों का जनाघ प्रति दो धर्म में होना आवश्यक है.

२७. किन्ही सार सलाहकार परिस्थिती में समस्त प्रतिनिधी मंडल की बैठक समस्त प्रतिनिधीयों के २ दस्तखतों से नोटिस मिलने पर भी समस्त प्रतिनिधी मंडल की बैठक कारखाना मंडल पंचायत के पंच महोदय को बुलाना आवश्यक हो, ऐसी बैठक का निरूप्य प्रस्ताव भी वैधानिक होगा.

२८. सार के प्रतिनिधी सारा पंचायत या कारखाना मंडल पंचायत पर अविश्वास का प्रस्ताव समस्त प्रतिनिधी मंडल की बैठक में रखा जाकर विचार किया जा सकता है, ऐसे प्रतिनिधी सारा पंचायत कारखाना मंडल पंचायत जिसे लिताफ अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ हो, उस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये उस स्थान पुनः जनाघ किया जावे, ऐसे अविश्वास के प्रस्ताव को २ वोट की आवश्यकता रही जावे.

२९. अगर कोई प्रतिनिधी मर जावे, कारखाने से काम छोड देवे तो उसके रिक्त स्थान का पुनः जनाघ किया जावे.

३०. मील कारखाने के अलावे मे सारा पंचायत कारखाना मंडल पंचायत अपना स्थानीय केन्द्र अधिक मंडल पंचायत के अलावा उस उद्योग से सम्बन्धित रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन भी सभा मीटिंग प्रचार, सैन्डिकल सदस्यता फन्ड उठा सकती है और पंचायतों के जनाघ में भी

अपने उन्नीसवार भी लडे करने को उन्हें अधिकार रहे.

३१. स्थानीय केन्द्र कमिश्नर मंडल पंचायत में स्थानीय समी उपायों को कारखाना मंडल पंचायत के प्रतिनिधियों के द्वारा जूने हुवे सदस्य हो. पिनकी तादाद कारखाना मंडलों के कुल सदस्यों की $\frac{2}{5}$ के बराबर होवे. और कम से कम ११ रखी जावे.

३२. माननीय सदस्य में स्थानीय केन्द्र कमिश्नर मंडल पंचायत में कुल माननीय सदस्य जो वास उस उपाय जन्दे के कमिश्नर भी नहीं हो मगर कमिश्नों की सेवा और महार का कार्य उस केन्द्र मंडल पंचायत के अनुशासन में रहकर करना चाहते हो. रह सकते हैं. ऐसे सदस्यों की तादाद ज्यादा से ज्यादा ३ रहेगी. जिनमें २ तो स्थानीय केन्द्र कमिश्नर मंडल पंचायत द्वारा और १ सरकार द्वारा नामजद किया जा सकता है.

३३. स्थानीय केन्द्र कमिश्नर मंडल पंचायत का एक अधिकार रहेगा.

३४. उसका कुल सर्व का $\frac{2}{5}$ राज्य सरकार के कैबिनेट डिपार्टमेंट द्वारा और $\frac{3}{5}$ सर्व कारखाना मंडल पंचायत उठायेगी.

३५. स्थानीय केन्द्र कमिश्नर मंडल पंचायत में के कुल पदाधिकारी इस प्रकार रहे.

१. अध्यक्ष : २. उपाध्यक्ष : ३. प्रधान मंत्री : ४. सहायक मंत्री : ५. प्रचार मंत्री : ६. क्लर्क : ७. सहायक : ८. क्लर्क : बाकी अन्य सदस्य रहेंगे. इन पदाधिकारियों का चुनाव स्थानीय केन्द्र कमिश्नर मंडल पंचायत के सभी सदस्य गण अपने वोटों से करें.

३६. इसके सभी पदाधिकारी सदस्य वैतनिक रूप में २४ घंटे समय देने वाले हो जिनका वैतन उनके कारखानों में उनकी नौकरी पर मिलने वाले वैतन के रूप में दिया जावे. और बाकी सदस्यों को उनके कारखाने के काम के वैतन का $\frac{2}{5}$ अलाउन्स दिया जावे. तथा कारखानेले पंचायत के कामवाकद हुटी लें पर उस दिन का पूरा अर्जाना दिया जावे.

३७. इसके सभी पदाधिकारी सदस्य जो कि होत टार्म पर होंगे उन्हें उस काम पर नियुक्ती तक कारखाने से उनके काम की हुटी रहेगी और उस पद से सेवा मुक्त होने पर पुनः अपने काम पर कारखाने में रख लिया जावेगा. उनकी नौकरी का कितना टूटा हुआ माना नहीं जावे.

३८. इस पंचायत की बैठक १५ दिन में एक बार हो. कायदा बैठक अध्यक्ष की वास उपायत से भी हुवा हो जा सके का नियम हो.

३९. इस पंचायत मर भी अधिकार का प्रस्ताव समस्त कारखानों की समस्त कारखाना मंडल पंचायतों और तादा पंचायतों को समस्त प्रतिनिधी मंडल की बैठक में या सकता है और विचार कर प्रस्ताव पास होने पर रिक्त स्थान की सेवा हुटी इस पंचायत का चुनाव पुनः किया जावे.

४०. स्थानीय केन्द्र कमिश्नर मंडल पंचायत का भी कार्य काल २ वर्ष का रहेगा. इसके बाद पुनः निर्वाचन होगा.

४१. स्थानीय केन्द्र कमिश्नर मंडल पंचायत के काम में

:क: जमिंदारों की मसालों के काम करना, उनकी मसालों को न मंगाने जागें कठाना सामुहिक समझौते करना,

:ख: साक्षात : डिपार्टमेंन्टल: पंचायत , फेक्टरी : कारखाना : मंडल पंचायतों के कामों की रिपोर्टें लेना, उनके कामों में मदद देना, जमिंदारों की शिकायतों एवं फरगदों सुलझाना,

:ग: जमिंदारों की मसालों के लिये कानून बनवाना,

:घ: जमिंदारों के लिये गृह निर्माण, कौशापरेटिव : सहकारी समितियां : दिल बस्ताव केंद्र, जमिंदार बालक बालिकाओं के लिये शिक्षण शालाए, बालवाड़ी, शिक्षण गृह, प्रवृत्ति गृह, जमिंदार कल्याण केंद्र, शौचोपयोगिक शिक्षणालय, खेल भुव, सिनेगृह, नाट्य गृह, फौजी बालिम, पुस्तकालय, स्वयं सेवक क्लब का निर्माण,

:ङ: जमिंदारों में शार्पिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, साध्यात्मिक पैना राष्ट्र पित्त में पैदा करना,

:च: राष्ट्र कल्याण और शान्ति काम के लिये प्रयत्न करना,

:छ: स्वायत्त शासन : नगर विकास : धारा समा : लोकमत में अपने उन्नीदवार लडे करना,

:ज : जमिंदारों की मसालों की मंगाने के लिये कन्सीलिटेशन अफसरों, वेलफेयर अफसरों, वेंच बौडों, पंच अदालतों, ट्रिब्यूनलों और स्पेसिट ट्रिब्यूनलों आदि सभी के दरवाजे बन्द हो जानेपर स्थानीय केंद्र जमिंदार मंडल पंचायत को काम शुरूआत पुकारने का अधिकार इराजित रहे,

४२. स्थानीय केंद्र जमिंदार मंडल पंचायतों पर सरकारी नियंत्रण या पदाय विस्तार नहीं रहेगा ऐसी पंचायतों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व रहेगा.

जन्म में राज्य सरकारों, केंद्रीय सरकार, सभी स्वायत्त की टैंड बुनियातों राजनैतिक संस्थाओं, कारखाना मालिकों, अन्य नागरिकों, जागरूक जनता एवं समस्त जमिंदारों से नियोजन है कि किस प्रकार देश की स्वतंत्रता के पक्षित १३ फी सदी लोगों को छोट का अधिकार था, वे १३ फी सदी व्यक्ति के छोटों से जुने हुवे व्यक्ति ही सारी जनतापर कानून बनाकर घोषित थे उसके बसले अब स्वतंत्रता के बाद भारतीय गवराज्य के संविधान के अंतुहार बालिम मताधिकार पर उनी हुवे सरकारें कायम की गई है, उन्हें ही देश का राज्य का प्रान्त का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है, तब फिर जमिंदारों में काम करने वाली १५ फी सदी सदस्य वाली टैंड बुनियात संस्था को ही सारे सौ फी सदी जमिंदारों का प्रतिनिधित्व करने के अधिकार की मान्यता कहां तक न्यायोपित्त हो सकती है, १५ फी सदी सदस्य वाली टैंड बुनियात को ही प्रतिनिधित्व के मान्यते ही अगर अंतंत्र है तब तो फिर विधान सभा, लोक सभा, स्थुनितीपालिटीज, आदि का चुनाव करने में लाखों, करोड़ों रुपयों का व्यय सर्व क्यों किया जावे ? देश की कौई भी राजनैतिक कल जिसके १५ फी सदी सदस्य ही उन्हें ही राज्य सभाने का अधिकार हमारे संविधान में क्यों नहीं रखा गया ? स्वतंत्र देश में जंहा पर बालिम

प्रताधिकार हो वहां ऐसी मान्यता स्थापित नहीं है,

अगर कहा जायें कि इस विधान के अनुसार प्रतिनिधि पंचायतों को जाने से फिर ट्रेड यूनियनों का महत्व कुछ नहीं रहता और ट्रेड यूनियनों की आवश्यकता नहीं यह प्रश्न भी उठाया जा सकता है कि यह विधान ट्रेड यूनियनों के अधिकारों पर चोट पहुंचाने वाला विधान होगा ?

इस प्रश्न का जवाब हो तथा उनकी सेवा समाधान के हेतु सिर्फ इतना नहीं ही निवेदन है कि इस विधान के तर्कों पर फर्क से सभी व्यापार की ट्रेड यूनियनों को काम करने की स्वतंत्रता मिलेगी, उन्हें उनके सिद्धान्त, कार्य क्षेत्रों को कसौटी पर रखने का मौका मिलता है, तथा जिस प्रकार नगर सचिवालयों, पंचायत सभा, लोक सभा, आदि में जन प्रतिनिधीत्व के लिये सभी पार्टी या अपने उम्मीदवार उभरे करती है उसी प्रकार यूनियनों के प्रतिनिधीत्व के लिये भी जनतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधीत्व के लिये हर एक रजिस्टर्ड यूनियनों को पंचायतों के चुनाव में अपने प्रतिनिधी उम्मीदवार उभरे करने का अधिकार मिलता है, इस विधान को गंभीरता पूर्वक अध्ययन करने से मालूम होगा कि उसके अन्त में सभी ट्रेड यूनियनों टूटने एवं महत्व हीन होने के बजाय ज्यादा उद्वृद्ध, बलवती तथा सक्रिय होगी,

वास्तव में राष्ट्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा लोकसभा, विधान सभा से विनम्र प्रार्थना है कि इस पर गंभीरता से सोच विचार कर इसे पास करने में सफलता मिले,

कमिश्नर व नुनियों

ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं, ट्रेड यूनियनों, पार्टियों एवं लोक सचिवों तथा जन संघ के हिमायतीयों से अपील है कि इस महत्व पूर्ण मामले पर अवश्य गौर करके किसी बहाने उसे नजर अन्धाकार करके पुरजोर कोशिश से इस विधान को पास कराने का प्रयास करें,

प्रेमचंद

बापसाह का सेक्टर

राधे 1915 आभारपाल

राधेलाल बायलवाल

दिनांक 26 मई 1948 ई.

शुक्लचन्द्र, मित्त दिन पाली

पारस लाल बजली का कमिश्नर

AMENDMENTS TO CONSTITUTION.

2. (e) (iii) Freedom of association/^{and} collective bargaining.
4. (e) Delete "or an equivalent etc."
- (g) Under 16 years.
- (k) Payment of wages to/^{women}workers 7 weeks before and 7 weeks after child birth.
- (o) Educational facilities including technical education.
6. (a) Rs.10/- for 200 membership and Rs.15/- up to 500 and 3 pies per membership above 500 with a minimum of Rs.20/-
9. General Council and Trade Groups
- (e) Cotton Textiles,
Jute "
Wool "
Silk "
- (p) Building, Wood, Tile and Cement and other building material industries.
- (q) Food group including, Hotel, Restaurants, Food manufacturing industries, beverages etc.
12. 30 members elected by the General Council by a system of cumulative voting.
13. (b) The General Council shall meet twice a year.
- (c) The Working Committee shall meet thrice a year.
20. *The general sessions of the AITUC shall be held at least once in every two years.*

AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION

I. ARTICLE 4

- (h) Add after 'housing' the words 'and education'
- (k) Line one: Delete the words 'six weeks' before 'after child-birth' and substitute 'eight weeks' in its place.
- (n) Delete the whole sentence and substitute the following:
"Effective control of workers and trade unions over Provident Fund, Social Insurance, housing and other welfare measures"

- K.B. Panikkaß.

ALL INDIA TRADE UNION CONGRESS
R. L. Trust Building
55, Girgaum Road
BOMBAY 4.

CONSTITUTIONAL AMENDMENTS ADOPTED BY THE 23rd
SESSION OF THE AITUC.

1. Delete Clause 5 (a) (iv) which reads as under:

"No Union should be affiliated to the AITUC which has not been in existence for at least one year".

2. Delete Clause 5 (b) and substitute the following:-

"The Working Committee of the AITUC shall have the authority of accepting or rejecting any application for affiliation from a Trade Union, provided, however, that in case of acceptance or rejection of any such application by the Working Committee, it will be open to the General Council or the General Body of the AITUC to confirm or set aside such a decision".

3. In Clause 7 (a) for line 1 and 2 substitute the following:

"The annual contribution shall be paid by the 30th of June each year".

4. Clause 15: Add clause 15 (c) as under:

"Emergency meeting of the Working Committee can be called by giving a notice of seven days."

5. Delete Clause 16 (a) and substitute the following:-

"One delegate for each Union having a membership of 200 or less and one additional delegate for every complete set of 200 members and a further delegate for the last fraction of 200, if the said last fraction consists of 100 or more members."

6. In Clause 16 (e) delete the words "for at least 12 months".

7. Delete Clause 25 and substitute the following:-

"Election of Delegates to International and other Conferences Delegates and advisers for the World Federation of Trade Unions and other international and national Conferences and meetings shall be ordinarily elected at meetings either of the General Council or of the Working Committee, whichever is being in session. In case of emergency, and when either the General Council or the Working Committee cannot be convened, decisions may be taken by circular to the members of the Working Committee."

"Ordinarily, each affiliated Union shall have the right to nominate candidates for election of the delegation; all nominations must reach the General Secretary within a fortnight from the date of the circulation of the notice".

8. Clause 27: Delete the words "shall" and substitute in its place "may".

9. Clause 28: "Emergency Decision: On all occasions of emergency decisions may be taken by the General Secretary in a meeting of the members of the Working Committee available at the headquarters. Other Working Committee members shall be posted with information of all such decisions taken by the General Secretary."

10. Clause 29: "Disciplinary Action: The General Council may take disciplinary action against any office bearer or a member of the General Council who acts in a way harmful to the interests of the I.TUC".

11. "Filling Up Vacancies. In case of a vacancy or vacancies from amongst the members of the Working Committee or in case of a vacancy of any of the office-bearers other than that of the President or the General Secretary, the Working Committee may fill up the vacancies by electing new members of Office-bearers as the case may be subject to the approval of the next meeting of the General Council. In case of vacancy in the post of the President or the General Secretary due to death or resignation, the General Council is authorised to fill up the vacancy and in case of vacancy due to detention, the General Council is empowered to elect persons to act in their place. The General Council may also fill up any vacancy in any Trade Group from amongst the members of that particular Trade Group".

kr.

ALL INDIA TRADE UNION CONGRESS CONSTITUTION.

1. Name. The name of the organisation shall be the All India Trade Union Congress (to be designated in abbreviated form as the A.I.T.U.C.).

Aims and Objects.

2. The objects of the A.I.T.U.C. shall be :
- (a) To establish Socialist State in India;
 - (b) To socialise and nationalise the means of production, distribution and exchange as far as possible;
 - (c) To ameliorate the economic and social conditions of the working class;
 - (d) To watch, promote, safeguard and further the interests, rights and privileges of the workers in all matters relating to their employment;
 - (e) To secure and maintain for the workers
 - (i) The freedom of speech;
 - (ii) The freedom of press;
 - (iii) The freedom of association;
 - (iv) The freedom of assembly;
 - (v) The right to strike, and
 - (vi) The right to work or maintenance.
 - (f) To support and actively participate in the struggle for India's political freedom, from the point of view of the working class;
 - (g) To co-ordinate the activities of the Labour Unions affiliated to the AITUC, and
 - (h) To abolish political or economic advantage based on caste, creed, community, race or religion.
3. The A.I.T.U.C. shall endeavour to further the aforesaid objects by all legitimate, peaceful and democratic methods such as legislation, education, propaganda, mass meetings, negotiations, demonstrations and, in the last resort, by strikes and similar other methods, as the AITUC may, from time to time, decide.

Demands.

4. The demands of the AITUC shall be :
- (a) A statutory enactment providing for a six-hours' working day;
 - (b) Minimum living wage;
 - (c) Weekly payment of wages;
 - (d) Equal wages for equal work, without racial or sex discrimination;
 - (e) One month's leave with full pay, or an equivalent amount of compensation when leave is not granted.
 - (f) Unemployment, sickness, old age, accident and maternity insurance;
 - (g) Pensions for widowed mothers and dependent children;
 - (h) Proper housing;
 - (i) Formation through Trade Unions of the workers' committees in factories, workshops, business houses and all other places where collective work is performed, with a view to control conditions of work, inside these places;
 - (j) Abolition of the employment of children under 15 years of age;

- (k) Payment of wages to women workers six weeks before and six weeks after child-birth;
- (l) Abolition of all other systems of recruiting labour, except through Trade Unions;
- (m) Abolition of fines and debts; and
- (n) Effective control of the subscribers over the Provident Funds.

Affiliation of Unions.

5. (a) The AITUC may affiliate to itself any bona fide Trade Union which satisfies the following conditions:-

- (i) The Trade Union seeking affiliation shall make an application according to the form.

Explanation:- A Trade Union is an organ of class struggle; its basic task, therefore, is to organise the workers for advancing and defending their rights and interests; and although collective bargaining is the necessary implication of a Trade Union and although in the transitional period to socialism, negotiations, representation, joint action and other methods of collective bargaining must remain an integral part of trade union activities, labour and capital cannot be reconciled within the capitalistic system.

- (ii) It shall pay an annual contribution and special levies, as provided in these rules.
- (iii) It shall send a copy of its rules and regulations, a list of its office-bearers, a copy of the statement of accounts for the official year, giving an average paying membership for the period, duly audited by a qualified auditor and such other information or materials as the General Secretary of the AITUC may require.
- (iv) The application for affiliation shall be forwarded through the Provincial Committee, wherever such a Committee exists, to the General Secretary of the AITUC, with remarks if any, made by the Provincial Committee regarding the eligibility of the Union for affiliation, under the Rules of the AITUC. Such applications shall be forwarded by the Provincial Committee to the General Secretary within a period of two months.
- (v) The minimum fee which a Union desiring affiliation to the AITUC shall charge to its members shall not be less than rupee one per year. The General Council, however, shall have power to permit a lesser membership fee in cases of unions consisting of workers from seasonal or sweated industries.

(b) The Working Committee of the AITUC shall have the authority of accepting or rejecting any application for affiliation from a Trade Union, provided, however, that in case of the acceptance or rejection of any such application by the Working Committee, it will be open to the General Council, or to the General Body of the A.I.T.U.C. to confirm or set aside such a decision.

(c) The General Council shall have power to disaffiliate any Union, which is proved to have been guilty of breaches of this Constitution, provided that it will be open to the General Body to affirm or set aside that decision.

Affiliation fees.

6. Each Affiliated Union shall pay to the AITUC.-

- (a) An annual contribution (i) of Rs.15/- for 500 membership and below (ii) and at the rate of three pies per member with a minimum of Rs.20/- for Unions with a membership above 500.
- (b) A delegation fee of Rs.2 per delegate, and
- (c) Such other levy as may be fixed by a majority of not less than 2/3rds of the members of the General Council.

7. (a) The annual contribution shall be paid by the 30th of June each year. The special contribution or levy shall become payable as and when fixed in each case. Non-payment of any contribution or levy that has become due shall disqualify the defaulting Union from voting at or participating in the meetings of the AITUC, or any of its constituent bodies, until the payment is made; the disqualification shall also apply to the voting on the circulars that may be issued by the Secretariat, till the fees are paid; provided that the Working Committee may, in special cases for reasons to be recorded, remit the disqualifications.

(b) A Union, when disqualified for non-payment of contributions or levies may be reaffiliated on payment of the arrears ~~xx~~ and the current fees.

(c) In case a Union is disqualified, within the meaning of clause(a), for a period of not less than twelve months, the General Secretary may issue a notice to the Union concerned to make good within three months, all the dues at the date of the notice. In case, the Union fails to pay all such arrears, demanded within the time given, it shall be liable for disaffiliation.

Composition of the A.I.T.U.C.

8. The A.I.T.U.C. shall consist of :

- (i) The affiliated Unions;
- (ii) The delegates assembled at the General or special Session;
- (iii) The General Council including the Office-bearers;
- (iv) The Working Committee of the General Council;
- (v) The Provincial Bodies.

General Council & Trade Groups.

9. (a) The General Council shall consist of :

- (i) A President
- (ii) Five Vice-Presidents
- (iii) A general secretary
- (iv) A Treasurer
- (v) Not more than four Assistant Secretaries, and
- (vi) Other members elected by the AITUC under the following Trade Groups:

- (a) Railways, (b) Shipping; (c) Transport other than Railways and Shipping; (d) Cotton Textiles; (e) Jute Textile;
- (f) Mining and Quarrying; (g) Engineering & allied Trades and Industries; (h) Printing and Paper; (i) Non-manual;
- (j) Agricultural; (k) Municipal; (l) Distributive; (m) General;
- (n) Tobacco; (o) Communications.

The General Council may determine the list of Trade Groups from time to time by addition, amalgamation or omission as deemed desirable.

(The new arrangement of Trade Groups shall come into operation after an interval of three months, after intimation of such a change to the Affiliated unions. The minimum membership for a Trade Group shall be 2,000. When membership in Unions in a group does not come upto 2,000, the Union will be included in the General Group).

(b) The Union shall, in its application for affiliation, state the particular Trade Group to which it would like to belong and the Working Committee shall allocate to such Union its appropriate Trade Groups, subject to the right of appeal to the General Council, whose decision in the matter shall be final.

(c) Delegates alone shall be eligible for election to the General Council. Election of membership of the General Council shall be made during the annual session of the AITUC, by the delegates present at the session, meeting separately in the Trade Groups as mentioned in clause 9(a), by the system of cumulative voting.

(d) Casual vacancies shall be filled at a meeting of the General Council from the Trade Group where vacancies have occurred.

(e) The representation ~~xx~~ of the different Trade Groups on the General

Council shall be on the following scale:

Two representatives for a Group with a membership upto and including 3,000;
Three representatives for a Group with a membership between 3,000 and 6,000;
Four representatives for a Group with a membership between 6,000 and 9,000;
Five representatives for a Group with a membership between 9,000 and 12,000;
Six representatives for a Group with a membership between 12000 and 16000;
Seven representatives for a Group with a membership between 16000 and 20000;
Eight Representatives for a Group with a membership between 20000 and 24000;
Nine representatives for a Group with a membership between 24000 and 30000;
Ten representatives for a Group with a membership between 30000 and 36000;
Eleven representatives for a Group with a membership between 36000 and 42000;
Twelve representatives for a Group with a membership between 42000 and 50000;
Thirteen representatives for a Group with a membership between 50000 and 60000;
One representative to be added for each 10,000 membership above 60,000.

10. A member of the General Council who ceases to be a member of any Trade Group on whose behalf he has been elected to the General Council, shall cease to be a member of the General Council.

11. The representatives of the Trade Groups elected on the General Council, in the manner prescribed in these rules, shall co-opt members on the Council, not necessarily connected with any trade union organisation but who have taken part in the trade union movement and whose presence on the Council may be considered essential in the interest of the Movement. The number of such co-opted members shall not be more than one-sixth of the total number of representatives of the affiliated organisations.

Working Committee.

12. There shall be a Working Committee of the General Council consisting of:

- (A) All office-bearers of the AITUC as ex-officio members;
- (B) Twenty members elected by the General Council by a system of cumulative voting.

Meeting.

13. (a) The A.I.T.U.C. shall meet once every year;
- (b) The General Council shall meet at least once a year;
- (c) The Working Committee shall meet twice a year.

14. The Working Committee shall have power to call a special session of the AITUC. On a requisition from the Unions representing 1/4th. of the total strength of the AITUC, the General Secretary shall, in consultation with the President, call a Special Session of the AITUC within six weeks of the receipt of the requisition, for the purpose of transacting the definite business mentioned in the requisition.

15. (a) Notice of the time and place of meeting of the Working Committee, General Council and General and Special Session of the AITUC, shall be given by the General Secretary.

(b) For the meeting of the Working Committee, at least 15 days' notice shall be given; for the meeting of the General Council and the General Session of the AITUC, at least a fortnight's and a month's notice respectively shall be given.

(c) Emergency meeting of the Working Committee can be called by giving a notice of seven days.

16. (a) For the General or the Special Session of the AITUC, the affiliated Unions shall be entitled to elect delegates on the following basis:-

One delegate for each union having a membership of 200 or less, and one additional delegate for every complete set of 200 members, and a further delegate for the last fraction of 200, if the said last fraction consists of 100 or more members.

(b) To ascertain the number of delegates which an Affiliated Union is

entitled to send to the AITUC, the basis shall be the number of paying members existing on the register of the Union, as disclosed in the balance sheet of the Union, for the year prior to the Session of the AITUC, duly certified by the auditor.

(c) An Affiliated Union shall furnish to the General Secretary the names and addresses of the delegates two weeks before the date fixed for the session of the AITUC.

(d) Delegate's card will be issued on production of a certificate of election by the Secretary of the Union concerned.

(e) No person who is neither an office-bearer of the Affiliated Union, nor a member of the Affiliated Union shall be entitled to be elected as a delegate of the AITUC.

(f) Propositions for the agenda of the General Session of the AITUC must be signed by the President or the Secretary of the Union sending them, and must reach the General Secretary of the AITUC, at least two weeks before the time fixed for the meeting of the AITUC.

(g) A Trade Union shall not be allowed to send more than five resolutions but in order that important labour questions may not be omitted from discussion at the Session, the General Council is empowered to place important propositions on the Agenda.

(h) At the meeting of the AITUC the official business shall have priority over other business.

17. On a motion being put to the Session of the AITUC, the President shall declare the result on a show of hands. But if any delegate demands a division, the voting shall be by Unions, and each Union is then entitled to as many votes as the number of delegates it is entitled to send as per rule 16 above. On a poll, the voting shall be by means of a card.

Questions for Decision.

17-A. Questions coming for decision before the Working Committee, the General Council and the Session of the AITUC, shall be decided by a majority of votes, provided, however, that questions of political nature, and those relating to strikes to be declared by the AITUC, and the affiliation of the AITUC to any foreign organisation shall be decided by a three-fourths majority.

Reception Committee.

18. (a) The Provincial Committee for the place where the Session is to be held, will form a Reception Committee for the purpose. In places where a Provincial Committee is not functioning, a committee appointed by affiliated unions of the place shall be the Reception Committee.

(b) The Reception Committee shall have power to collect funds for the expenses of the AITUC Session. After meeting the expenses of the Session, if there be any surplus, the same shall belong to the Provincial or local Trade Union organisation of the place, where the Session is held.

Quorum.

19. The quorum at the sessions of the AITUC and at the meetings of the General Council and the Working Committee shall be one-third of the delegates or members of the respective bodies.

Time of the Session.

20. The General Session of the AITUC shall be ordinarily held in December.

Powers of General Council and Working Committee.

21. (a) The General Council shall have the authority to take all proper steps to carry out the work of the AITUC in accordance with the Constitution;

(b) The Working Committee shall have the authority:

- (i) To take all proper steps for carrying out the resolutions passed at the previous Session of the AITUC;
- (ii) To deal with any emergency that arises during the year, affecting the interests of the working class; and
- (iii) Generally to advance and further the aims and objects of the AITUC.

General Secretary's Report.

22. The General Secretary shall present a report of the work done during the year by the Working Committee and the General Council and an audited statement of accounts and balance sheet, duly certified by auditors.

Election of Office-bearers.

23. Office-bearers shall be elected by the annual General Session, after having received nominations duly proposed and recommended by one or more delegates. Nominees must be persons, who are either delegates at the session, or are retiring office-bearers.

President of Sessions.

24. The outgoing President shall preside at the General Session, and any Special Session that may be held during his term of office.

Election of delegates to International & Other Conferences.

25. Delegates and advisers to the World Federation of Trade Unions and other international and national Conferences and meetings shall be ordinarily elected at meetings of the General Council or the Working Committee, whichever is being in session. In case of emergency, and when either the General Council or the Working Committee cannot be convened, decisions may be taken by circular to the members of the Working Committee.

International Affiliation.

26. The AITUC may be affiliated to such International bodies as have same or similar object and methods.

Political Committed.

27. The Working Committee may appoint, from among its members, a political committee consisting of seven members. The Committee shall endeavour:

- (i) To encourage the Affiliated Unions to build up their political funds;
- (ii) To organise, in consultation with the General Council, elections to the local bodies and the legislatures;
- (iii) To keep a watch over the taxation proposals of the Central and Local Govts and over the development of the labour legislation in India, from the point of view of the working class;
- (iv) To initiate legislation in the interests of the working class; and
- (v) To do such other political propaganda in consultation with the Working Committee, as may not be inconsistent with this Constitution.

Bye-Laws.

28. The General Council have power to make bye-laws, not inconsistent with this Constitution, and in particular on questions relating to :

(a) the election of delegates, (b) the submission of returns and (c) the affiliation fees.

Provincial and Regional Units.

29. (a) Affiliated unions in every Provincial administrative unit, shall form a Provincial Trade Union Congress Committee. Every Union in the Province, affiliated to the AITUC, shall automatically form a part of the Provincial Committee, and a Union which has not secured affiliation to the AITUC cannot become a member of the Provincial Committee. The Provincial Committee and the individual Unions shall have power to manage their affairs according to their own rules, subject to the provisions of this Constitution.

Where a Provincial Administrative Unit consists of two or more linguistic units, separate Provincial Trade Union Committees may be permitted to be formed by the General Council.

(b) The Provincial Committee may enrol as Associate Member any Union, which has not secured affiliation to the AITUC but which proposes to observe the constitution of the AITUC, except sub-rule a(iv) of Rule 6. The Associate Unions will have no power of voting at the meeting of Provincial Committees, nor will they be entitled to have any privileges of Affiliated Unions, under the constitution of the AITUC.

(c) Regional Trade Union Councils: Where the General Council finds that if affiliated Trade Unions in an area are grouped together (taking into consideration homogeneity of language and nearness or affinity of industrial units in the area) in a Regional Trade Union Council, the work of the organisation will be more efficiently done, the General Council may authorise the Provincial Committee to organise such Trade Union Councils. The Regional Trade Union Councils will have their own working constitution, which will be consistent with that of the AITUC and of the Provincial Committees. In matters of representations etc., to the Government concerning regions, the Regional Council may directly approach the Government but when such matters concern the province as a whole, the Regional Council will only function through the Provincial Committees.

Amendment.

30. It shall be open to the AITUC on the report of the General Council to make any additions or changes ~~x~~ in this Constitution by a majority of 3/4th votes.

CONSTITUTIONAL AMENDMENTS ADOPTED BY THE 23RD SESSION OF THE A.I.T.U.C.

1. Clause 28: "Emergency Decision: On all occasions of emergency decisions may be taken by the General Secretary in a meeting of the members of the Working Committee available at the headquarters. Other Working Committee members shall be posted with information of all such decisions taken by the General Secretary".
2. Clause 29: "Disciplinary Action: The General Council may take disciplinary action against any office bearer or member of the General Council who acts in a way harmful to the interests of the AITUC".
3. "Filling up Vacancies: In case of a vacancy or vacancies from amongst the members of the Working Committee or in case of a vacancy of any of the Office-bearers other than that of the President or the General Secretary, the Working Committee may fill up the vacancies by electing new members of Office-bearers as the case may be subject to the approval of the next meeting of the General Council. In case of vacancy in the post of the President or the General Secretary due to death or resignation, the General Council is authorised to fill up the vacancy and in case of vacancy due to detention, the General Council is empowered to elect persons to act in their place. The General Council may also fill up any vacancy in any Trade Group from amongst the members ~~at~~ of that particular Trade Group".

.....

Note: Proposed amendments to the above Constitution will be circulated later.